



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 09, 2018/वैशाख 19, 1940

No. 176]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 09, 2018/VAISAKHA 19, 1940

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड**

**अधिसूचना**

मुम्बई, 09 मई, 2018

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड**

**[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018**

**सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10.**—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

2. विशेष रूप से इन विनियमों में जैसा प्रावधान (उपबंध) किया गया है उसके सिवाय, वे 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त (लागू) होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-

(क) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (यख) में, -

i. परिभाषा के पश्चात् तथा मौजूदा परंतुक से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) से संबंध रखने वाले और सूचीबद्ध एंटीटी में 20% या उससे अधिक की शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) रखने वाले किसी व्यक्ति या एंटीटी को संबद्ध (संबंधित) पक्षकार समझा जाएगा:”

- ii. मौजूदा परंतुक में, जो दूसरे परंतुक के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा, शब्द “यह” के पश्चात् तथा शब्द “कि” से पूर्व शब्द “और” अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) विनियम 15 में, उप-विनियम (2) में तथा उप-विनियम (2) के खंड (ख) के परंतुक में, अंक “17” के पश्चात् चिह्न और अंक “, 17क” अंतःस्थापित किया जाएगा तथा अंक “24” के पश्चात् चिह्न और अंक “, 24क” अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ग) विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, -

i. खंड (ख) में, -

1. उप-खंड (ii) में, शब्दों “न रहा हो” के पश्चात्, शब्द और चिह्न “अथवा जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) का सदस्य न हो या न रहा हो” अंतःस्थापित किए जाएंगे।
2. मौजूदा उप-खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -  
“(viii) जो किसी ऐसी दूसरी कंपनी में गैर-स्वतंत्र निदेशक (नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) न हो, जिसके बोर्ड में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी का कोई गैर-स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक हो।”

ऊपर खंड (i) में जिन संशोधनों का उल्लेख है, वे 1 अक्तूबर, 2018 से प्रवृत्त (लागू) होंगे।

ii. खंड (ग) में, शब्द “बीस” शब्द “दस” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

iii. खंड (घ) में, शब्द और चिह्न “कार्यपालक निदेशकों से एक स्तर नीचे के प्रबंध-मंडल के सभी सदस्य समाविष्ट होंगे, जिनमें सभी कार्यों के प्रमुख सम्मिलित हैं” निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे -

“मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक (जिसमें वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंधक भी शामिल हैं, जो बोर्ड का हिस्सा न हों) से एक स्तर नीचे के प्रबंध-मंडल के सभी सदस्य समाविष्ट होंगे और खास तौर पर इसमें कंपनी सचिव तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे।”

(घ) विनियम 17 में, -

i. उप-विनियम (1) में, -

1. खंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक तथा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे -

“परंतु यह कि शीर्ष 500 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) में 1 अप्रैल, 2019 तक और शीर्ष 1000 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) में 1 अप्रैल, 2020 तक कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक हो;

**स्पष्टीकरण:** शीर्ष 500 और 1000 एंटीटियों का निर्धारण ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के आधार पर किया जाएगा;”

2. मौजूदा खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(ग) शीर्ष 1000 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों के निदेशक मंडल में (1 अप्रैल, 2019 से) और शीर्ष 2000 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों के निदेशक मंडल में (1 अप्रैल, 2020 से) कम से कम छह निदेशक होंगे।

**स्पष्टीकरण:** शीर्ष 1000 और 2000 एंटीटियों का निर्धारण ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के आधार पर किया जाएगा।”

ii. मौजूदा उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(1क) कोई भी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी गैर-कार्यपालक निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) के रूप में तब तक किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी या किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक पद पर नहीं रखेगी जो पचहत्तर वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जब तक कि इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित न कर दिया जाए, और ऐसे मामले में ऐसे प्रस्ताव के नोटिस के साथ लगाए जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में यह उल्लेख किया जाएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का औचित्य क्या है।”

iii. उपरोक्तानुसार अंतःस्थापित किए गए नए उप-विनियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(1ख) 1 अप्रैल, 2020 से, शीर्ष 500 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी सूचीबद्ध एंटिटी के बोर्ड का अध्यक्ष -

(क) गैर-कार्यपालक निदेशक हो ;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन परिभाषित शब्द “नातेदार” की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक निदेशक से संबंध न रखता हो;

परंतु यह कि यह उप-विनियम उन सूचीबद्ध एंटिटियों पर लागू नहीं होगा जिनमें स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए शेयरधारिता स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न) के अनुसार कोई संप्रवर्तक (प्रमोटर) न हों।

स्पष्टीकरण: शीर्ष 500 एंटिटियों का निर्धारण ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के आधार पर किया जाएगा।”

iv. मौजूदा उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(2क) 1 अप्रैल, 2019 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों के और 1 अप्रैल, 2020 से शीर्ष 2000 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम उसकी कुल संख्या का एक-तिहाई या तीन निदेशक होगा (जो भी ज्यादा हो) और जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होगा;

**स्पष्टीकरण I** – शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या दूसरे श्रव्य-दृश्य (ऑडियो-विजुअल) साधनों के जरिए भाग लेने वाले निदेशकों की गिनती भी ऐसे कोरम के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

**स्पष्टीकरण II** - शीर्ष 1000 और 2000 एंटिटियों का निर्धारण ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के आधार पर किया जाएगा।”

v. उप-विनियम (6) में, -

1. खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(गक) विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन प्रत्येक वर्ष लिया जाएगा, जिसमें किसी एक गैर-कार्यपालक निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) को देय वार्षिक पारिश्रमिक सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को देय कुल वार्षिक पारिश्रमिक के पचास प्रतिशत से अधिक हो जाता हो, और ऐसे पारिश्रमिक के ब्यौरे दिए जाएँगे।”

2. मौजूदा खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(इ) जो कार्यपालक निदेशक (एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हों या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के सदस्य हों, उन्हें फीस या प्रतिकर (कॉम्पन्सेशन) साधारण बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी लेकर अदा किया जाएगा, यदि -

(i) ऐसे कार्यपालक निदेशक को अदा किया जाने वाला वार्षिक पारिश्रमिक 5 करोड़ रुपये से या सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के शुद्ध लाभ के 2.5 प्रतिशत से (जो भी अधिक हो) अधिक हो जाए; या

(ii) जहाँ एक से अधिक ऐसे निदेशक हों, वहाँ ऐसे निदेशकों को अदा किया जाने वाला कुल वार्षिक पारिश्रमिक सूचीबद्ध एंटीटी के शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाए;

परंतु यह कि इस प्रावधान (उपबंध) के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन ऐसे निदेशक की पदावधि समाप्त होने तक ही मान्य रहेगा।

**स्पष्टीकरण:** इस खंड के प्रयोजनार्थ, शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार की जाएगी।”

vi. उप-विनियम (10) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(10) स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन संपूर्ण निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होगा -

(क) निदेशकों के कार्य-निष्पादन का; और

(ख) इन विनियमों में यथा उल्लिखित स्वतंत्रता संबंधी मानदंडों की पूर्ति का और प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) से उनकी स्वतंत्रता का;

परंतु यह कि उपरोक्त मूल्यांकन में वे निदेशक भाग नहीं लेंगे जिनका मूल्यांकन किया जाना हो।”

vii. मौजूदा उप-विनियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“11. साधारण बैठक की कार्यसूची के अनुरूप प्रत्येक विशेष मद हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 की उप-धारा (1) के अनुसार सूचना (नोटिस) के साथ लगाए जाने वाले विवरण (स्टेटमेंट) के अंतर्गत प्रत्येक विशेष मद के संबंध में शेयरधारकों को की गई बोर्ड की सिफारिश का भी स्पष्ट उल्लेख होगा।”

(ड) मौजूदा विनियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

#### “17क. निदेशक पद धारण करने की अधिकतम संख्या

निदेशक पद धारण करने की अधिकतम संख्या [जिनमें उनके द्वारा धारित कोई आनुकल्पिक (वैकल्पिक) निदेशक पद भी शामिल हैं] के संबंध में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों के निदेशक निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे -

(1) कोई व्यक्ति 1 अप्रैल, 2019 से आठ से अधिक सूचीबद्ध एंटीटियों में निदेशक नहीं होगा और 1 अप्रैल, 2020 से सात से अधिक सूचीबद्ध एंटीटियों में निदेशक नहीं होगा :

परंतु यह कि कोई व्यक्ति सात से अधिक सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों में स्वतंत्र निदेशक नहीं होगा।

(2) उपरोक्त के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी में पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंध निदेशक हो, तीन से अधिक सूचीबद्ध एंटीटियों में स्वतंत्र निदेशक नहीं होगा।

इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, ऐसी सूचीबद्ध एंटीटियों की ही गिनती की जाएगी जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों और जिनमें कोई व्यक्ति निदेशक / स्वतंत्र निदेशक हो।”

(च) विनियम 19 में, -

क. मौजूदा उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(2क) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक के लिए कोरम या तो दो सदस्यों का होगा या समिति के एक-तिहाई सदस्यों का होगा, जो भी ज्यादा हो, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होगा।”

ख. मौजूदा उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(3क) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।”

(छ) विनियम 20 में, -

क. उप-विनियम (1) में, शब्दों “की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था” के लिए शब्द “के हित के विभिन्न पहलुओं” प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ख. मौजूदा उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(2क) कम से कम तीन निदेशक, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो, समिति के सदस्य होंगे।”

ग. उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, -

“(3) हितधारक संबंध समिति का अध्यक्ष प्रतिभूति धारकों (सिक्यूरिटीज़ होल्डर) के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक साधारण बैठकों में उपस्थित रहेगा।”

घ. उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(3क) हितधारक संबंध समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।”

(ज) विनियम 21 में, -

क. मौजूदा उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(3क) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।”

ख. उप-विनियम (4) में, शब्दों “जैसा वह ठीक समझे” के पश्चात् और चिह्न “।” से पूर्व, चिह्न और शब्द “, ऐसे कार्य में विशेष रूप से साइबर सुरक्षा को शामिल किया जाएगा” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ग. उप-विनियम (5) में, अंक “100”, अंक “500” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

(झ) विनियम 23 में, -

क. उप-विनियम (1) में, चिह्न “।”, शब्दों और चिह्नों “जिसमें निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित स्पष्ट सीमा-रेखाएँ (श्रेस्होल्ड लिमिट) शामिल होंगी, और निदेशक मंडल द्वारा ऐसी नीति की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्षों में कम से कम एक बार की जाएगी और उसे तदनुसार अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा :” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ख. उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(1क) उपरोक्त के होते हुए भी, ऐसे किसी संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) जिसमें ब्रांड के इस्तेमाल या रॉयल्टी के संबंध में संबद्ध पक्षकार को भुगतान किए गए हों, को उस स्थिति में महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि किया जाने वाला (किए जाने वाले) संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) अलग-अलग या वित्तीय वर्ष के दौरान हुए पिछले संव्यवहारों के साथ मिलकर, सूचीबद्ध एंटीटी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के वार्षिक समेकित व्यापारवर्त (टर्नओवर) के दो प्रतिशत से अधिक हो जाता हो (हो जाते हों)।”

- ग. उप-विनियम (4) में, शब्द “संबद्ध पक्षकार ऐसे संकल्पों के संबंध में होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे” के लिए शब्द “कोई भी संबद्ध पक्षकार ऐसे संकल्पों को अनुमोदन दिए जाने के संबंध में मतदान नहीं करेगा” प्रतिस्थापित हो जाएँगे।
- घ. उप-विनियम (7) में, शब्दों “मतदान में हिस्सा नहीं लेंगी” के लिए शब्द “सुसंगत (संबद्ध) संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) को अनुमोदन दिए जाने के संबंध में मतदान नहीं करेंगी” प्रतिस्थापित हो जाएँगे।
- ङ. मौजूदा उप-विनियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(9) सूचीबद्ध एंटीटी छमाही के अपने एकल (स्टैन्ड अलोन) और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, समेकित आधार पर संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों (रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) के प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), वार्षिक परिणामों हेतु संबद्ध लेखा मानकों के अंतर्गत निर्धारित फॉर्मेट में, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी और उन्हें अपने वेबसाइट पर डालेगी (प्रकाशित करेगी)।”

यह संशोधन 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली छमाही से प्रवृत्त (लागू) होगा।

(ज) विनियम 24 में, -

- क. मौजूदा उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(1) सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक असूचीगत महत्वपूर्ण समनुपंगी (अनलिस्टिड मटिरियल सब्सिडयरी), चाहे भारत में निगमित हो या न हो, के निदेशक मंडल में निदेशक होगा।

**स्पष्टीकरण** - इस प्रावधान (उपबंध) के प्रयोजनार्थ, विनियम 16 में दी हुई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, शब्दों “महत्वपूर्ण समनुपंगी” से वह समनुपंगी (सब्सिडयरी) अभिप्रेत होगी जिसकी आय या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ठीक पहले के लेखा वर्ष में सूचीबद्ध एंटीटी और उसकी समनुपंगियों (सब्सिडयरी) की क्रमशः समेकित आय या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के वीस प्रतिशत से अधिक हो।”

- ख. उप-विनियम (4) के स्पष्टीकरण में, शब्द “असूचीगत” के पश्चात् दिए हुए शब्दों और चिह्नों “महत्वपूर्ण (तात्त्विक / मटिरियल)” का लोप हो जाएगा।

(ट) मौजूदा विनियम 24 के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“24क. सेक्रेटेरियल ऑडिट

प्रत्येक सूचीबद्ध एंटीटी तथा भारत में निगमित उसकी असूचीगत महत्वपूर्ण समनुपंगियाँ (मटिरियल अनलिस्टिड सब्सिडयरी) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष से सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाएँगी और अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ पेशेवर कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) द्वारा दी गई सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट [जो ऐसे प्ररूप (फॉर्म) में होगी जो निर्धारित किया जाए] लगाएँगी।”

(ठ) विनियम 25 में, -

- i. मौजूदा उप-विनियम (1), निम्नलिखित नए उप-विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(1) 1 अक्तूबर, 2018 से कोई भी व्यक्ति सूचीबद्ध एंटीटी के स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर न तो आनुकल्पिक (वैकल्पिक) निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और न ही आनुकल्पिक (वैकल्पिक) निदेशक के पद पर बना रहेगा।”

- ii. मौजूदा उप-विनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्, -

“(8) प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड की उस पहली बैठक में जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होने वाली बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी भी परिस्थितियों में कोई ऐसा बदलाव आए जिससे स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति प्रभावित हो सकती हो, यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि वह विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में यथा निर्धारित स्वतंत्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करता है और यह कि उसे

ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति की जानकारी नहीं है, जो विद्यमान हो या जिससे यह संभावना हो कि वह परिस्थिति या स्थिति निष्पक्ष स्वतंत्र निर्णय लेने और बिना किसी बाहरी दबाव के कर्तव्यों का निर्वहन करने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

(9) सूचीबद्ध एंटीटी का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) उप-विनियम (8) के अधीन स्वतंत्र निदेशक द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणा और प्रस्तुत किए गए पुष्टीकरण की सत्यता को पूरी तरह से आँकने के पश्चात् उसे रिकॉर्ड करेगा।

(10) 1 अक्तूबर, 2018 से, पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध एंटीटियाँ, अपने सभी स्वतंत्र निदेशकों हेतु निदेशकों और अधिकारियों का बीमा ('डी एवं ओ बीमा') करवाएँगी, उतनी राशि का और उतने जोखिमों का जैसा उसके निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाए।”

(ड) विनियम 29 में, उप-विनियम (1) में, खंड (च) में दिए हुए परंतुक का लोप 1 अक्तूबर, 2018 से हो जाएगा।

(ढ) विनियम 32 में, मौजूद उप-विनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(7क) जहाँ एंटीटी ने अधिमानी आबंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) या अर्हित संस्था नियोजन (क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशन्स प्लेटमेंट) के जरिए निधियाँ जुटाई हों (फंड जुटाया हो), वहाँ सूचीबद्ध एंटीटी प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के दौरान ऐसी निधियों (फंड) के उपयोग की जानकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में तब तक प्रकट करती रहेगी, जब तक कि उन निधियों (उस फंड) का पूरी तरह उपयोग न कर लिया जाए।”

(ण) विनियम 33 में, उप-विनियम (3) में, -

i. खंड (ख) में,

क. शब्दों और चिह्नों “वित्तीय परिणाम भी निम्नलिखित के अध्यक्षीन, प्रस्तुत कर सकेगी :” के लिए, शब्द और चिह्न “समेकित वित्तीय परिणाम भी प्रस्तुत करेगी।” प्रतिस्थापित हो जाएँगे ;

ख. उप-खंड (i) एवं (ii) का लोप हो जाएगा।

ii. खंड (ड) में, शब्दों “तिमाही की बाबत लेखापरीक्षित” के पश्चात् और शब्दों “वित्तीय परिणाम” से पूर्व, शब्द “या सीमित समीक्षा (लिमिटेड रिव्यू) किए हुए” अंतःस्थापित किए जाएँगे।

iii. मौजूदा खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खंड अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्,-

“(छ) सूचीबद्ध एंटीटी छमाही के अपने एकल (स्टैन्ड अलोन) और समेकित वित्तीय परिणामों के भागस्वरूप, एक नोट के माध्यम से, छमाही के नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण भी प्रस्तुत करेगी।

(ज) सूचीबद्ध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि तिमाही के समेकित वित्तीय परिणामों के प्रयोजनार्थ, क्रमशः समेकित आमदनी (रेविन्यू), आस्तियों (असेट्स) और लाभों प्रत्येक के कम से कम अस्सी प्रतिशत की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) करवाया हो या अलेखापरीक्षित परिणामों के मामले में, सीमित समीक्षा (लिमिटेड रिव्यू) करवाई हो।

(झ) सूचीबद्ध एंटीटी, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के परिणामों में, एक नोट के माध्यम से, यह तथ्य प्रकट करेगी कि उस तिमाही के परिणामों में पिछली अवधियों से संबंधित महत्वपूर्ण समायोजनों का कुल कितना प्रभाव रहा।”

त. विनियम 33 में, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(8) सूचीबद्ध एंटीटी का कानूनी लेखापरीक्षक उन सभी एंटीटियों / कंपनियों के लेखों की सीमित समीक्षा (लिमिटेड रिव्यू) करेगा, जिनके लेखे लेखा मानक 21 (एएस 21) के अनुसार सूचीबद्ध एंटीटी के साथ समेकित किए जाने हों [इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) के अनुसार]।”

(थ) विनियम 34 में, -

i. मौजूदा उप-विनियम (1) निम्नलिखित नए उप-विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(1) सूचीबद्ध एंटीटी -

(क) वार्षिक साधारण बैठक की सूचना (नोटिस) के साथ-साथ शेयरधारकों को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति उस दिन के बीतने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी और अपने वेबसाइट पर भी डालेगी, जिस दिन वह उसे अपने शेयरधारकों को प्रेषित करना शुरू करे;

(ख) वार्षिक रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के बदलाव होने की दशा में, बदलावों के विवरणों और स्पष्टीकरण के साथ संशोधित प्रति, वार्षिक साधारण बैठक के बाद 48 घंटों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी और अपने वेबसाइट पर भी डालेगी।”

ऊपर खंड (थ) में जिस संशोधन का उल्लेख किया गया है, वह 31 मार्च, 2019 को और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दाखिल की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में लागू होगा।

(द) विनियम 36 में, -

i. उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्दों “इस प्रयोजनार्थ” के लिए, शब्द “या तो सूचीबद्ध एंटीटी के पास या किसी निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के पास” प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

ऊपर खंड (द) (i) में जिस संशोधन का उल्लेख किया गया है, वह 31 मार्च, 2019 को और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दाखिल की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में लागू होगा।

ii. मौजूदा उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्, -

“(4) इन संशोधनों के अधिसूचित होने की तारीख से तत्काल प्रभाव से -

(क) सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को किए जाने वाले प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) के अनुसार *एक्सबीआरएल* फॉर्मेट में होंगे; और

(ख) सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को किए जाने वाले प्रकटीकरण तथा सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा अपने वेबसाइट पर डाले जाने वाले प्रकटीकरण ऐसे फॉर्मेट में होंगे जिनमें उपयोगकर्ता (यूजर) संबंध जानकारी *सर्चिंग टूल* के जरिए आसानी से ढूँढ़ पाए :

परंतु यह कि *सर्चबल फॉर्मेट* में प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ ऐसे प्रकटीकरण ऐसे फॉर्मेटों में करना कानूनन जरूरी हो जो *सर्चबल फॉर्मेट* न भी हों, जैसे स्कैन किए हुए दस्तावेजों की प्रतियाँ।

(5) वार्षिक साधारण बैठक, जहाँ कानूनी लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) [स्टैट्यूटरी ऑडिटर] की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव हो, के लिए शेयरधारकों को भेजी जाने वाली सूचना (नोटिस) में, सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) के भागस्वरूप, निम्नलिखित प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) शामिल होंगे :

(क) कानूनी लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) को अदा किए जाने हेतु प्रस्तावित फीस के साथ-साथ नियुक्ति की शर्तें आदि और नए लेखापरीक्षक के मामले में, ऐसे लेखापरीक्षक को अदा की जाने वाली फीस और पुराने लेखापरीक्षक को अदा की गई फीस में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसका तर्काधार ;

(ख) नियुक्ति की सिफारिश का आधार, जिसमें शामिल हैं - उस कानूनी लेखापरीक्षक (उन कानूनी लेखापरीक्षकों) से संबंधित विवरण और उनके *क्रेडेंशियल* जिसे (जिन्हें) नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव हो।”



(ध) विनियम 44 में, -

- (i) शीर्षक "शेयरधारकों द्वारा मतदान" के लिए, शीर्षक "शेयरधारकों की बैठकें और मतदान" से प्रतिस्थापित हो जाएगा; और
- (ii) मौजूदा उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-विनियम (5) तथा उप-विनियम (6) अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, -

“(5) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार, बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर शीर्ष 100 सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से पाँच महीनों की अवधि के भीतर अपनी वार्षिक साधारण बैठकें करेंगी।

(6) शीर्ष 100 सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटियाँ वार्षिक साधारण बैठकों की कार्यवाहियों का *वन-वे लाइव वेबकास्ट* करेंगी।

**स्पष्टीकरण:** शीर्ष 100 एंटीटियों का निर्धारण ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर किया जाएगा।”

(न) विनियम 46 में, उप-विनियम (2) में, -

- i. शब्दों "अपने वेबसाइट पर" के लिए, शब्द "अपने वेबसाइट पर एक अलग खंड में" प्रतिस्थापित हो जाएंगे ;
- ii. मौजूदा खंड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, -

“(द) 1 अक्तूबर, 2018 से, एंटीटी द्वारा उसकी सभी बकाया लिखतों (आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रुमेंट्स) के संबंध में ली गई सभी क्रेडिट रेटिंगों (साख निर्धारण) को, उनमें कोई भी संशोधन होते ही, तुरंत अद्यतन (अपडेट) किया जाए।

(ध) संबद्ध वित्तीय वर्ष के संबंध में सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटी की प्रत्येक समनुषंगी (सब्सिडियरी) के पृथक् लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उस वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले ही अपलोड कर दिए जाएँ, जो अन्य बातों के साथ-साथ उस वित्तीय वर्ष के लेखों पर विचार करने के लिए बुलाई गई हो।”

(प) अनुसूची-II में, -

क. भाग-ग में, खंड क में, मौजूदा उप-खंड (20) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(21) नियंत्री (धारिता / होल्डिंग) कंपनी द्वारा समनुषंगी (सब्सिडियरी) को दिए गए उन ऋणों और/या उन अग्रिमों (एडवांस) के उपयोग की / समनुषंगी (सब्सिडियरी) में किए गए उस निवेश की समीक्षा करना, जो 100 करोड़ रुपये या समनुषंगी (सब्सिडियरी) के आस्ति आकार (असेट साइज़) के 10% (जो भी कम हो) से अधिक हो, जिसमें इस प्रावधान के लागू होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार मौजूदा ऋण / अग्रिम / निवेश भी शामिल हैं।”

ख. भाग-घ में, -

- i. खंड क में, मौजूदा उप-खंड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
- “(6) ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल को किसी भी रूप में अदा किए जाने वाले सभी प्रकार के पारिश्रमिक की सिफारिश बोर्ड को करना।”
- ii. खंड ख के अंतर्गत दी गई विषय-वस्तु निम्नलिखित नए प्रावधानों से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात् -

“समिति की भूमिका में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित शामिल होगा:

(1) सूचीबद्ध एंटीटी के प्रतिभूति धारकों (सिक्यूरिटी होल्डर) की शिकायतों [जिनमें शेयरों के अंतरण (ट्रांसफर) / पारेषण (ट्रांसमिशन), वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए प्रमाणपत्र /

प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट प्रमाणपत्र) जारी करने, साधारण बैठकों आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं] का निवारण करना।

- (2) शेयरधारकों द्वारा मताधिकारों के प्रभावी प्रयोग के संबंध में किए गए उपायों की समीक्षा करना।
- (3) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों (सर्विस स्टैण्डर्ड्स) के अनुसरण की समीक्षा करना।
- (4) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा अदावाकृत लाभांशों (वे लाभांश जिनका दावा न किया गया हो) की राशि कम करने के संबंध में और यह सुनिश्चित करने के संबंध में कि कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्टें / नोटिस (जो कानूनी तौर पर दिए जाने जरूरी हों) समय पर मिले, किए गए विभिन्न उपायों और उठाए गए कदमों की समीक्षा करना।"

ग. भाग-ड में, खंड घ का लोप हो जाएगा।

उपरोक्त खंड (ग) में जिस संशोधन का उल्लेख किया गया है, वह 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

(फ) अनुसूची-III में, भाग-क में, खंड क - "वे घटनाएँ जिनका प्रकटीकरण विनियम 30 के उप-विनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट महत्ता (तात्त्विकता) संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू किए बिना किया जाएगा", के अंतर्गत, मौजूदा उप-खंड 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्, -

"(7क) सूचीबद्ध एंटीटी के लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में, लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के कारण (जिनका उल्लेख उक्त लेखापरीक्षक ने किया हो) सूचीबद्ध एंटीटियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को, यथासंभव शीघ्रता से किंतु लेखापरीक्षक की ओर से ऐसे कारण प्राप्त होने से चौबीस घण्टों के भीतर, प्रकट किए जाएँगे।

(7ख) लेखापरीक्षक का त्यागपत्र और त्यागपत्र के कारण: सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के स्वतंत्र निदेशक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में, त्यागपत्र की तारीख से सात दिनों के भीतर, सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएँगे:

- i. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिए गए त्यागपत्र के कारण (जिनका उल्लेख उक्त निदेशक ने किया हो) सूचीबद्ध एंटीटियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किए जाएँगे।
- ii. स्वतंत्र निदेशक, कारणों का विस्तार से उल्लेख करने के साथ-साथ, इस बात का भी पुष्टीकरण प्रदान करेगा कि जिन कारणों का उल्लेख किया गया है उनके अलावा कोई भी दूसरे महत्वपूर्ण कारण नहीं हैं।
- iii. उपरोक्तानुसार स्वतंत्र निदेशक द्वारा दिया गया पुष्टीकरण भी सूचीबद्ध एंटीटियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किया जाएगा और साथ ही वे कारण भी सूचित किए जाएँगे जिनका ऊपर उप-खंड (i) के अनुसार विस्तार से उल्लेख किया गया है।"

(ब) अनुसूची-IV में, भाग-क में, खंड खख में, मौजूदा उप-खंड (i) एवं (ii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएँगे, अर्थात्,-

"i. प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) अनिवार्य रूप से प्राक्कलन करेगा और लेखापरीक्षक (ऑडिटर) उसकी समीक्षा करेगा तथा तदनुसार रिपोर्ट करेगा;

ii. ऊपर दी हुई किसी बात के होते हुए भी, प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) को कामकाज चलाने में आ रही दिक्कतों या न्यायाधीन मामलों के संबंध में प्राक्कलन न करने की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसे मामले में प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) उसके कारणों का उल्लेख करेगा और लेखापरीक्षक उनकी समीक्षा करेगा तथा तदनुसार रिपोर्ट करेगा।"

(भ) अनुसूची-V में, -

क. 'संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण' से संबंधित भाग-क में, मौजूदा खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(2क) सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटी का, संप्रवर्तक (प्रमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति या एंटीटी, जिसकी सूचीबद्ध एंटीटी में शेयरधारिता 10% या उससे अधिक हो, के साथ किए गए संव्यवहारों (ट्रांजेक्शन्स) का प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) वार्षिक परिणामों हेतु सुसंगत (संबद्ध) लेखा मानकों के अंतर्गत निर्धारित फॉर्मेट में किया जाएगा।”

ख. 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण' से संबंधित भाग-ख में, खंड 1 में, मौजूदा उप-खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

“(झ) मुख्य वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण बदलावों (अर्थात् ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या उससे अधिक के बदलाव) के ब्यौरों के साथ-साथ उनके संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण, जिनमें शामिल हैं:

- (i) डेटर टर्नओवर
- (ii) इनवेंटरी टर्नओवर
- (iii) इंटरैस्ट कवरेज रेशियो
- (iv) करंट रेशियो
- (v) डैट-इक्विटी रेशियो
- (vi) ओपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%)
- (vii) नेट प्रॉफिट मार्जिन (%)

या किसी क्षेत्र (सेक्टर) विशेष के वैसे ही अनुपात, जो भी लागू हों।

(ज) ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना में रिटर्न ऑन नेटवर्थ में हुए किसी बदलाव के ब्यौरों के साथ-साथ उसके संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण।”

ग. 'कंपनी शासन संबंधी रिपोर्ट' से संबंधित भाग-ग में, -

i. खंड (2) में, -

उप-खंड (ग) में, शब्दों "अध्यक्ष हो" के पश्चात्, चिह्न, शब्द और अंक ", और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से, उन सूचीबद्ध एंटीटियों के नामों का अलग से प्रकटीकरण जहाँ व्यक्ति निदेशक हो, और साथ ही निदेशक-पद की श्रेणी का प्रकटीकरण" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

1. मौजूदा उप-खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,

“(ज) निदेशक मंडल की कार्यकुशलता / विशेषज्ञता / क्षमता को दर्शाने वाला चार्ट या मैट्रिक्स जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:

- (i) 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से, निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) द्वारा यथा निर्धारित प्रमुख कार्यकुशलताओं / विशेषज्ञता / क्षमताओं [जो उसके कारबार तथा क्षेत्र (क्षेत्रों / सेक्टर) के संदर्भ में कारगर ढंग से कामकाज चलाने के लिए जरूरी हों] की सूची और यह भी बताया जाए कि बोर्ड के पास वास्तव में कितनी कार्यकुशलता / विशेषज्ञता / क्षमता है; और
- (ii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से, उन निदेशकों के नाम बताए जाएँ जिनके पास ऐसी कार्यकुशलता / विशेषज्ञता / क्षमता हो।

- (झ) इस बात का पुष्टीकरण कि बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) से स्वतंत्र हैं।
- (ञ) जो स्वतंत्र निदेशक अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही त्यागपत्र दे दे उसके त्यागपत्र के कारण (विस्तार से), और साथ ही ऐसे निदेशक की ओर से इस बात का पुष्टीकरण कि जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा कोई दूसरे महत्वपूर्ण कारण नहीं है।”
- ii. खंड (9) में, मौजूदा उप-खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
- “(थ) संबद्ध वित्तीय वर्ष के दौरान एंटीटी द्वारा ली गई सभी क्रेडिट रेटिंगों (साख निर्धारण) की और साथ ही उनमें हुए किन्हीं संशोधनों की सूची, जो ऐसी एंटीटी के सभी ऋण लिखतों (डैट इंस्ट्रुमेंट्स) के संबंध में अथवा सूचीबद्ध एंटीटी के किसी *फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोग्राम* या किसी स्कीम या प्रस्ताव (प्रोपोजल) के संबंध में ली गई हों, जिनके माध्यम से भारत या विदेश में फंड (निधियाँ) जुटाया गया/जाना हो।”
- iii. खंड (10) में, मौजूदा उप-खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, -
- “(ज) अधिमानी आबंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट) अथवा अर्हित संस्था नियोजन (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन्स प्लेसमेंट) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण, जैसा कि विनियम 32 (7क) में निर्धारित किया गया है।
- (झ) पेशेवर कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) की ओर से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक (डायरेक्टर) को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या निदेशक पद पर बने रहने से विवर्जित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- (ञ) जहाँ बोर्ड ने, संबद्ध वित्तीय वर्ष में, बोर्ड की किसी समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार न किया हो, जिसे स्वीकार करना अनिवार्य हो, तो ऐसे में उसे उसके कारणों सहित प्रकट किया जाए:
- परंतु यह कि यह खंड केवल वहाँ लागू होगा जहाँ समिति की सिफारिश आदि निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु अपेक्षित हो और वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ संबंधित समिति का पूर्व अनुमोदन इन विनियमों के अधीन किसी भी संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) के लिए अपेक्षित हो।
- (ट) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी और उसकी समनुपंगियों (सहायक कंपनियों/सब्सिडियरीज़) द्वारा सभी सेवाओं के लिए, समेकित आधार पर कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) को और उस नेटवर्क फर्म / नेटवर्क एंटीटी की सभी एंटीटियों को अदा की गई कुल फीस, जिसका कानूनी लेखापरीक्षक हिस्सा हो।”

जैसा अन्यथा उल्लेख किया गया है उसके सिवाय, अनुसूची-V में किए गए संशोधन 31 मार्च, 2019 को और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दाखिल की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में लागू होंगे।

[विज्ञापन III/4/असा. /52/2018]

अजय त्यागी, अध्यक्ष

#### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :

- क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
- ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
- ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
- घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
- ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
- च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 9th May, 2018

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.**—In exercise of the powers conferred by section 11, sub section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018.
2. Save as otherwise specifically provided for in these regulations, they shall come into force with effect from April 1, 2019.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, -
  - (a) in regulation (2), in sub-regulation (1), in clause (zb), -
    - ii. the following proviso shall be inserted after the definition and before the existing proviso, namely, -
 

“Provided that any person or entity belonging to the promoter or promoter group of the listed entity and holding 20% or more of shareholding in the listed entity shall be deemed to be a related party.”
    - iii. in the existing proviso, which shall be renumbered as the second proviso, the word “further” shall be inserted after the word “Provided” and before the word “that”.
  - (b) in regulation 15, in sub-regulation (2) as well as in the proviso to clause (b) of sub-regulation (2), the figure “17A” shall be inserted after the figure “17” and the figure “24A” be inserted after the figure “24”.
  - (c) in regulation (16), in sub-regulation (1), -
    - i. in clause (b), -

1. in sub-clause (ii), the words “or member of the promoter group of the listed entity” shall be inserted after the words “associate company”.
2. after the existing sub-clause (vii), the following new sub-clause shall be inserted, namely,-  
“(viii) who is not a non-independent director of another company on the board of which any non-independent director of the listed entity is an independent director:”

The aforesaid amendments mentioned in clause (i) shall come into force with effect from October 1, 2018.

- ii. in clause (c), the word “twenty” shall be substituted with the word “ten”.
- iii. in clause (d), the words “executive directors, including all functional heads” shall be substituted with the following –

“chief executive officer/managing director/whole time director/manager (including chief executive officer/manager, in case they are not part of the board) and shall specifically include company secretary and chief financial officer:”

(d) in regulation 17, -

- i. in sub-regulation (1), -

1. in clause (a), the following proviso and explanation shall be inserted-

“Provided that the Board of directors of the top 500 listed entities shall have at least one independent woman director by April 1, 2019 and the Board of directors of the top 1000 listed entities shall have at least one independent woman director by April 1, 2020;

Explanation: The top 500 and 1000 entities shall be determined on the basis of market capitalisation, as at the end of the immediate previous financial year.”

2. after the existing clause (b), the following new clause shall be inserted, namely,-

“(c) The board of directors of the top 1000 listed entities (with effect from April 1, 2019) and the top 2000 listed entities (with effect from April 1, 2020) shall comprise of not less than six directors.

Explanation: The top 1000 and 2000 entities shall be determined on the basis of market capitalisation as at the end of the immediate previous financial year.”

- ii. after the existing sub-regulation (1), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(1A) No listed entity shall appoint a person or continue the directorship of any person as a non-executive director who has attained the age of seventy five years unless a special resolution is passed to that effect, in which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such a person.”

- iii. after the newly inserted sub-regulation (1A) as above, the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(1B). With effect from April 1, 2020, the top 500 listed entities shall ensure that the Chairperson of the board of such listed entity shall -

(a) be a non-executive director;

(b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term “relative” defined under the Companies Act, 2013:

Provided that this sub-regulation shall not be applicable to the listed entities which do not have any identifiable promoters as per the shareholding pattern filed with stock exchanges.

Explanation - The top 500 entities shall be determined on the basis of market capitalisation, as at the end of the immediate previous financial year.”

- iv. after the existing sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(2A) The quorum for every meeting of the board of directors of the top 1000 listed entities with effect from April 1, 2019 and of the top 2000 listed entities with effect from April 1, 2020 shall be one-third of its total strength or three directors, whichever is higher, including at least one independent director;

**Explanation I** – For removal of doubts, it is clarified that the participation of the directors by video conferencing or by other audio-visual means shall also be counted for the purposes of such quorum.

**Explanation II** - The top 1000 and 2000 entities shall be determined on the basis of market capitalisation, as at the end of the immediate previous financial year.”

v. in sub-regulation (6), -

1. after clause (c), the following new sub-clause shall be inserted, namely,-

“(ca) The approval of shareholders by special resolution shall be obtained every year, in which the annual remuneration payable to a single non-executive director exceeds fifty per cent of the total annual remuneration payable to all non-executive directors, giving details of the remuneration thereof.”

2. after the existing clause (d), the following new clause shall be inserted, namely,-

“(e) The fees or compensation payable to executive directors who are promoters or members of the promoter group, shall be subject to the approval of the shareholders by special resolution in general meeting, if-

(i) the annual remuneration payable to such executive director exceeds rupees 5 crore or 2.5 per cent of the net profits of the listed entity, whichever is higher; or

(ii) where there is more than one such director, the aggregate annual remuneration to such directors exceeds 5 per cent of the net profits of the listed entity:

Provided that the approval of the shareholders under this provision shall be valid only till the expiry of the term of such director.

Explanation: For the purposes of this clause, net profits shall be calculated as per section 198 of the Companies Act, 2013.”

vi. the sub-regulation (10) shall be substituted with the following, namely, -

“(10) The evaluation of independent directors shall be done by the entire board of directors which shall include -

(a) performance of the directors; and

(b) fulfillment of the independence criteria as specified in these regulations and their independence from the management:

Provided that in the above evaluation, the directors who are subject to evaluation shall not participate.”

vii. after the existing sub-regulation 10, the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

“11. The statement to be annexed to the notice as referred to in sub-section (1) of section 102 of the Companies Act, 2013 for each item of special business to be transacted at a general meeting shall also set forth clearly the recommendation of the board to the shareholders on each of the specific items.”

(e) after the existing regulation 17, the following new regulation shall be inserted, namely, -

**“17A. Maximum number of directorships.**

The directors of listed entities shall comply with the following conditions with respect to the maximum number of directorships, including any alternate directorships that can be held by them at any point of time -

(1) A person shall not be a director in more than eight listed entities with effect from April 1, 2019 and in not more than seven listed entities with effect from April 1, 2020:

Provided that a person shall not serve as an independent director in more than seven listed entities.

(2) Notwithstanding the above, any person who is serving as a whole time director / managing director in any listed entity shall serve as an independent director in not more than three listed entities.

For the purpose of this sub-regulation, the count for the number of listed entities on which a person is a director/ independent director shall be only those whose equity shares are listed on a stock exchange.”

- (f) in regulation 19, -
- a. after the existing sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-  
“(2A) The quorum for a meeting of the nomination and remuneration committee shall be either two members or one third of the members of the committee, whichever is greater, including at least one independent director in attendance.”
  - b. after the existing sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -  
“(3A) The nomination and remuneration committee shall meet at least once in a year.”
- (g) in regulation 20, -
- a. in sub-regulation (1), for the words “the mechanism of redressal of grievances” the words “various aspects of interest” shall be substituted.
  - b. after the existing sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -  
“(2A) At least three directors, with at least one being an independent director, shall be members of the Committee.”
  - c. sub-regulation (3) shall be substituted with the following, -  
“(3) The Chairperson of the Stakeholders Relationship Committee shall be present at the annual general meetings to answer queries of the security holders.”
  - d. after sub-regulation 3, the following new sub-regulation shall be inserted, namely -“(3A) The stakeholders relationship committee shall meet at least once in a year.”
- (h) in regulation 21, -
- a. after the existing sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-  
“(3A) The risk management committee shall meet at least once in a year.”
  - b. in sub-regulation (4), after the words “as it may deem fit” and before the symbol “.”, the words “such function shall specifically cover cyber security” shall be inserted.
  - c. in sub-regulation (5), the figure “100” shall be substituted with the figure “500”.
- (i) in regulation 23, -
- a. in sub-regulation (1), the words “including clear threshold limits duly approved by the board of directors and such policy shall be reviewed by the board of directors at least once every three years and updated accordingly” shall be inserted after the words “related party transactions” and before the symbol “.”.
  - b. after sub-regulation (1), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-  
“(1A) Notwithstanding the above, a transaction involving payments made to a related party with respect to brand usage or royalty shall be considered material if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceed two percent of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity.”
  - c. in sub-regulation (4), the words “the related parties shall abstain from voting on” shall be substituted with the words “no related party shall vote to approve”.
  - d. in sub-regulation (7), the words “abstain from voting” shall be substituted with the words “not vote to approve the relevant transaction”.
  - e. after the existing sub-regulation (8), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -  
“(9) The listed entity shall submit within 30 days from the date of publication of its standalone and consolidated financial results for the half year, disclosures of related party transactions on a consolidated basis, in the format specified in the relevant accounting standards for annual results to the stock exchanges and publish the same on its website.”
- The amendment shall come into force with effect from the half year ending March 31, 2019.
- (j) in regulation 24, -
- a. the existing sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, -  
“(1) At least one independent director on the board of directors of the listed entity shall be a director on the board of directors of an unlisted material subsidiary, whether incorporated in India or not.

**Explanation-** For the purposes of this provision, notwithstanding anything to the contrary contained in regulation 16, the term “material subsidiary” shall mean a subsidiary, whose income or net worth



exceeds twenty percent of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.”

- b. in the Explanation to sub-regulation (4), the word “material” appearing after the word “unlisted” shall be omitted.

- (k) after the existing regulation 24, the following new regulation shall be inserted, namely,-

“24A. Secretarial Audit.

Every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake secretarial audit and shall annex with its annual report, a secretarial audit report, given by a company secretary in practice, in such form as may be specified with effect from the year ended March 31, 2019.”

- (l) in regulation 25, -

- i. the existing sub-regulation (1) shall be substituted with the following new sub-regulation, namely, -

“(1) No person shall be appointed or continue as an alternate director for an independent director of a listed entity with effect from October 1, 2018.”

- ii. after the existing sub-regulation 7, the following new sub-regulations shall be inserted, namely, -

“(8) Every independent director shall, at the first meeting of the board in which he participates as a director and thereafter at the first meeting of the board in every financial year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his status as an independent director, submit a declaration that he meets the criteria of independence as provided in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 16 and that he is not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated, that could impair or impact his ability to discharge his duties with an objective independent judgment and without any external influence.

(9) The board of directors of the listed entity shall take on record the declaration and confirmation submitted by the independent director under sub-regulation (8) after undertaking due assessment of the veracity of the same.

(10) With effect from October 1, 2018, the top 500 listed entities by market capitalization calculated as on March 31 of the preceding financial year, shall undertake Directors and Officers insurance (‘D and O insurance’) for all their independent directors of such quantum and for such risks as may be determined by its board of directors.”

- (m) in regulation 29, in sub-regulation (1), in clause (f), the proviso thereto shall be omitted with effect from October 1, 2018.

- (n) in regulation 32, after the existing sub-regulation (7), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(7A) Where an entity has raised funds through preferential allotment or qualified institutions placement, the listed entity shall disclose every year, the utilization of such funds during that year in its Annual Report until such funds are fully utilized.”

- (o) in regulation 33, in sub-regulation (3), -

- i. in clause (b), -

- a. the word ‘may’ shall be replaced with the word ‘shall’ ;
- b. the words and symbol “subject to following:” shall be substituted with the symbol “.” ; and
- c. sub-clauses (i) and (ii) shall be omitted.

- ii. in clause (e), the words “or limited reviewed” shall be inserted after the words “audited” and before the words “financial results”.

- iii. after the existing clause (f), the following new clauses shall be inserted, namely, -

“(g) The listed entity shall also submit as part of its standalone and consolidated financial results for the half year, by way of a note, statement of cash flows for the half-year.

(h) The listed entity shall ensure that, for the purposes of quarterly consolidated financial results, at least eighty percent of each of the consolidated revenue, assets and profits, respectively, shall have been subject to audit or in case of unaudited results, subjected to limited review.

(i) The listed entity shall disclose, in the results for the last quarter in the financial year, by way of a note, the aggregate effect of material adjustments made in the results of that quarter which pertain to earlier periods.”

(p) in regulation 33, the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(8) The statutory auditor of a listed entity shall undertake a limited review of the audit of all the entities/ companies whose accounts are to be consolidated with the listed entity as per AS 21 in accordance with guidelines issued by the Board on this matter.”

(q) in regulation 34, -

i. the existing sub-regulation (1) shall be substituted with the following new sub-regulation, namely, -

“(1) The listed entity shall submit to the stock exchange and publish on its website-

(a) a copy of the annual report sent to the shareholders along with the notice of the annual general meeting not later than the day of commencement of dispatch to its shareholders;

(b) in the event of any changes to the annual report, the revised copy along with the details of and explanation for the changes shall be sent not later than 48 hours after the annual general meeting.”

The amendment at clause (q) shall be applicable in respect of the Annual report filed for the year ended March 31, 2019 and thereafter.

(r) in regulation 36, -

i. in sub-regulation (1), in clause (a), the words “ for the purpose” shall be omitted and the words “either with the listed entity or with any depository” shall be inserted.

The amendment at clause (r)(i) shall be applicable in respect of the Annual report filed for the year ended March 31, 2019 and thereafter.

ii. after the existing sub-regulation (3), the following new sub-regulations shall be inserted, namely, -

“(4) The disclosures made by the listed entity with immediate effect from date of notification of these amendments-

(a) to the stock exchanges shall be in XBRL format in accordance with the guidelines specified by the stock exchanges from time to time; and

(b) to the stock exchanges and on its website, shall be in a format that allows users to find relevant information easily through a searching tool:

Provided that the requirement to make disclosures in searchable formats shall not apply in case there is a statutory requirement to make such disclosures in formats which may not be searchable, such as copies of scanned documents.

(5) The notice being sent to shareholders for an annual general meeting, where the statutory auditor(s) is/are proposed to be appointed/re-appointed shall include the following disclosures as a part of the explanatory statement to the notice:

(a) Proposed fees payable to the statutory auditor(s) along with terms of appointment and in case of a new auditor, any material change in the fee payable to such auditor from that paid to the outgoing auditor along with the rationale for such change;

(b) Basis of recommendation for appointment including the details in relation to and credentials of the statutory auditor(s) proposed to be appointed.”

(s) in regulation 44, -

(i) the title ‘Voting by shareholders’ shall be replaced with the title ‘Meetings of shareholders and voting’ ; and

(ii) after the existing sub-regulation (4), the following new sub-regulations (5) and (6) shall be inserted, namely, -

“(5) The top 100 listed entities by market capitalization, determined as on March 31<sup>st</sup> of every financial year, shall hold their annual general meetings within a period of five months from the date of closing of the financial year.

(6) The top 100 listed entities shall provide one-way live webcast of the proceedings of the annual general meetings.

**Explanation:** The top 100 entities shall be determined on the basis of market capitalisation, as at the end of the immediate previous financial year.”

(t) in regulation 46, in sub-regulation (2), -

- i. for the words “on its website”, the words “under a separate section on its website” shall be substituted;
- ii. after the existing clause (q), the following new clauses shall be inserted, namely, -
 

“(r) With effect from October 1, 2018, all credit ratings obtained by the entity for all its outstanding instruments, updated immediately as and when there is any revision in any of the ratings.

(s) separate audited financial statements of each subsidiary of the listed entity in respect of a relevant financial year, uploaded at least 21 days prior to the date of the annual general meeting which has been called to inter alia consider accounts of that financial year.”

(u) in Schedule II, -

- a. in Part C, in clause A, after the existing sub-clause (20), the following new sub-clause shall be inserted, namely, -
 

“(21) reviewing the utilization of loans and/ or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding rupees 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans / advances / investments existing as on the date of coming into force of this provision.”
- b. in Part D, -
  - i. in clause A, after the existing sub-clause (5), the following new sub-clause shall be inserted, namely, -
 

“(6) recommend to the board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management.”
  - ii. the contents under clause B shall be substituted with the following new provisions, namely, -
 

“The role of the committee shall *inter-alia* include the following:

    - (1) Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
    - (2) Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
    - (3) Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
    - (4) Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.”
- c. in Part E, clause D shall be omitted.

The amendment in clause c. above shall come into effect from April 1, 2020.

(v) in Schedule III, in Part A, under the Clause A dealing with ‘Events which shall be disclosed without any application of the guidelines for materiality as specified in sub-regulation (4) of Regulation (30)’, after the existing sub-clause 7, the following new sub-clauses shall be inserted, namely, -

“(7A) In case of resignation of the auditor of the listed entity, detailed reasons for resignation of auditor, as given by the said auditor, shall be disclosed by the listed entities to the stock exchanges as soon as possible but not later than twenty four hours of receipt of such reasons from the auditor.

(7B) Resignation of auditor including reasons for resignation: In case of resignation of an independent director of the listed entity, within seven days from the date of resignation, the following disclosures shall be made to the stock exchanges by the listed entities:

- i. Detailed reasons for the resignation of independent directors as given by the said director shall be disclosed by the listed entities to the stock exchanges.
- ii. The independent director shall, along with the detailed reasons, also provide a confirmation that there is no other material reasons other than those provided.
- iii. The confirmation as provided by the independent director above shall also be disclosed by the listed entities to the stock exchanges along with the detailed reasons as specified in sub-clause (i) above.”

(w) in Schedule IV, in Part A, in clause BB, the existing sub-clauses (i) and (ii) thereunder shall be substituted with the following, namely,-

- “i. The management shall mandatorily make an estimate which the auditor shall review and report accordingly.
- ii. Notwithstanding the above, the management may be permitted to not provide estimate on matters like going concerns or *sub-judice* matters; in which case, the management shall provide the reasons and the auditor shall review the same and report accordingly.”

(x) in Schedule V, -

- a. in Part A dealing with ‘Related Party Disclosure’, after the existing clause 2, the following new clause shall be inserted, namely,-

“(2A) Disclosures of transactions of the listed entity with any person or entity belonging to the promoter/promoter group which hold(s) 10% or more shareholding in the listed entity, in the format prescribed in the relevant accounting standards for annual results.”

- b. in Part B dealing with ‘Management Discussion and Analysis’, in clause 1, after the existing sub-clause (h), the following new sub-clauses shall be inserted, namely,-

“(i) details of significant changes (i.e. change of 25% or more as compared to the immediately previous financial year) in key financial ratios, along with detailed explanations therefor, including:

- (i) Debtors Turnover
- (ii) Inventory Turnover
- (iii) Interest Coverage Ratio
- (iv) Current Ratio
- (v) Debt Equity Ratio
- (vi) Operating Profit Margin (%)
- (vii) Net Profit Margin (%)

or sector-specific equivalent ratios, as applicable.

(j) details of any change in Return on Net Worth as compared to the immediately previous financial year along with a detailed explanation thereof.”

(c) in Part C dealing with ‘Corporate Governance Report’, -

i. in clause (2), -

- 1. in sub-clause (c), after the word “chairperson”, the symbol and words “, and with effect from the Annual Report for the year ended 31st March 2019, including separately the names of the listed entities where the person is a director and the category of directorship” shall be inserted.

- 2. after the existing sub-clause (g), the following new sub-clauses shall be inserted, namely, -

“(h) A chart or a matrix setting out the skills/expertise/competence of the board of directors specifying the following:

- (i) With effect from the financial year ending March 31, 2019, the list of core skills/expertise/competencies identified by the board of directors as required in the context of its business(es) and sector(s) for it to function effectively and those actually available with the board; and
- (ii) With effect from the financial year ended March 31, 2020, the names of directors who have such skills / expertise / competence

(i) confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.

(j) detailed reasons for the resignation of an independent director who resigns before the expiry of his tenure along with a confirmation by such director that there are no other material reasons other than those provided.”

ii. in clause (9), after the existing sub-clause (p), the following new sub-clause shall be inserted, namely, -

“(q) list of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad.”

iii. in clause (10), after the existing sub-clause (g), the following new sub-clauses shall be inserted, namely, -

“(h) Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A).

(i) a certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

(j) where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the relevant financial year, the same to be disclosed along with reasons thereof:

Provided that the clause shall only apply where recommendation of / submission by the committee is required for the approval of the Board of Directors and shall not apply where prior approval of the relevant committee is required for undertaking any transaction under these Regulations.

(k) total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part.”

Save as specified otherwise, the amendments to Schedule V shall be applicable in respect of Annual reports filed for the year ended March 31, 2019 and thereafter.

[ADVT. III/4/Exty./52/2018]

AJAY TYAGI, Chairman

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2<sup>nd</sup> September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
  - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
  - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
  - c) July 08, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
  - d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
  - e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.

March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.